वर्ष	प्रति वर्ष दालों का प्रति व्यक्ति उत्पादन किलोग्राम में
1960-61	28 8
1961-62	25 9
1962-63	25 0
1963-64	21 4
1964-65	25 7
1965-66	20 2
1966-67	16 6
1967-68	23 5
1968-69	19 9
1969-70	21 7
1970-71	21 4
1971-72	19 7
1972-73	17 2
1973-74	17 0
1974-75	16 7
1975-76	21 3
1976-77	17 9

टिप्पणी —दालो का प्रति व्यक्ति उत्पादन दालो के उत्पादन मे आबादी का भाग दे कर निकाला गया है । वर्ष 1951-52 मे 1964-65 तक के वर्षो के दौरान दालो के उत्पादन का अनुमान सूचकाको के आधार पर समायोजित किया गया है, जिनमे अनमानो के क्षेत्र तथा उनकी विधियो के परिवर्तन को भी ध्यान मे रखा गया है । आबादी के अनमान प्रति वर्ष की 1 जुलाई से सम्बन्धित है ।

राष्ट्रीय आवास नीति

9559. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाच वर्षों मे सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय आवास योजना को 31 मार्च, 1978 तक अन्तिम रूप न देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने नगर तथा ग्रामी ण क्षेत्रों की राज्यवार आवास आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है और इस आवश्यकता को पूरा करने पर कितना व्यय होगा, यदि हा, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार को राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों की अलग अलग आवास आवश्यकताओं की जानकारी है और क्या सरकार इसको पूरा करने के लिए किसी सम्बन्धित योजना पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) मूलत , आवास राज्य क्षेत्र का विषय है और केवल बागान कर्मचारियो की सहायता प्राप्त आवास योजना ही केन्द्रीय क्षेत्र में है । केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधिया समेकित ऋणो तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताएं स्वयं निर्धारित करने मे स्वतंत्र है , तथापि. आवास के क्षेत्र में भावी कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) ऐसा आवास कार्यक्रम चलाना जिस का उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि में पिछले बकाया को पूरा करना तथा जनसंख्या के बढ़ जाने के कारण

अतिरिक्त मांग को पूरा करना और अनुपयोगी मकानों को बदलना;

(ii) सरकारी निधियों को कम आय वाले परिवारों के लिए ही उपयोग करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गए संसाधनों से बडी संख्या में रिहायशी मकान बनाए जा सकें;

(iii) प्राइवेट सेक्टर के बडी संख्या मे मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना ।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की माग तथा इस माग को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई समिति नही बनाई है । तथापि, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लगाये गये एक अनुमान के अनुसार पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय अर्थात 1-4-1974 को 156 लाख मकानों की कमी थी । जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों मे 118 लाख मकानों, नगरीय क्षेत्रों में 38 लाख मकानो की कमी थी । 20 वर्ष की अवधि में पिछले बकाया को खत्म करने और जनसंख्या बढ जाने के कारण अतिरिक्त मांग को पूरा करने और तथा अनुपयोगी मकानों को बदलने के आवास कार्यक्रम में प्रतिवर्ष 475 लाख मकानो का निर्माण किया जाएगा जिसमे 350 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों 125 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में बनाये जायेंगे ।

गन्दी बस्तियों का बढ़ना रोका जाना

9560. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों तथा महानगर क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ती जा रही गन्दी बस्तियों को रोकने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं ;

(ख) यदि हा, तो उनकी मुख्य बाते क्या हैं ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1977-78 में गन्दी बस्तियों का बढ़ना किस सीमा तक सफलता-पूर्वक रोका गया है ; और

(घ) बड़े शहरों तथा महानगर कस्बों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या में गत तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) जबकि गन्दी बस्तियो की वृद्धि को रोकना सामाजार्थिक विकास के एक भाग के रूप में एक लम्बी अवधि का उद्देश्य है तथापि मौजूदा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है ।

(घ) इस बारे मे कोई आकड़े उपलब्ध नही हैं ।

Posts of Head Clerks in Department of Town and Country Planning Organisation

9561. **SHRI M. A. HANNAN ALHAJ:** Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to Unstarred Question No. 2636 replied on 13th March, 1978 regarding Head Clerks officiating as Investigators in the Department of Town and Country Planning Organisation and state:

(a) whether the organisation has requested the appropriate authorities to sanction more posts of Head Clerks as required by them;